रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 20, 1969 (अग्रहायण 29, 1891)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 20, 1969 (AGRAHAYANA 29, 1891)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 15 नवम्बर, 1969 तक प्रकाशित किये गये हैं :

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 15th November 1969 :

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)

——Nil——

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिए।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	849
भाग I—खंड 2—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1403
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1215
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	3815

	Page
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	849
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1403
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Non-statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1215
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	3815

	पृष्ठ
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं ..	5297
भाग II—खंड 4—रक्षा मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	629
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1283
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	463
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं..	125
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	715
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	245
पूरक संख्या 51—	
13 दिसम्बर 1969 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	2181
22 नवम्बर 1969 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बिमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़	2195

	Page
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	5297
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	629
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1283
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	463
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	125
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	715
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	245
SUPPLEMENT No. 50—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 6th December 1969 ..	2181
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 15th November 1969	2195

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

---

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 1969

सं० 67-प्रेज/69.—राष्ट्रपति मणिपुर राईफल्स के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

श्री एल० बीरा सिंह,
हवलदार सं० 1096,
2री बटालियन, मणिपुर राईफल्स,
इम्फाल ।

अधिकारी का नाम तथा पद

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

29 जनवरी, 1969 को विद्रोहियों के एक बड़े गिरोह ने मोंघलम गांव पर आक्रमण किया और ग्राम स्वयं सेवक दल के सदस्यों की कुछ राईफलें ले कर भाग गए । श्री एल० बीरा सिंह, हवलदार, के कमान में मणिपुर राईफल की दूसरी बटालियन की एक प्लाटून को विद्रोहियों को रोकने तथा उन राईफलों को बरामद करने के लिये नियुक्त किया गया । 4 फरवरी, 1969 को, गिरोह की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित ग्राम मोलकोट में होने की सूचना मिली । संख्या में कम और सीमित मात्रा में गोला बारूद होने पर भी प्लाटून निडर होकर मोलकोट ग्राम की ओर बढ़ी । ग्राम के निकट पहुंचने पर एक विद्रोही संतरी दिखाई दिया । श्री बीरा सिंह चुपके से उस संतरी को काबू में करने के उद्देश्य से आगे बढ़े । ऐसा करते समय उन्हें एक लड़की ने देखा जो चिल्ला उठी । संतरी भी सावधान हो गया । किन्तु श्री बीरा सिंह अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किये बिना संतरी पर झपटे और उसे काबू में कर लिया । अन्य विद्रोही लड़की की चिल्लाहट और हवलदार बीरा सिंह और संतरी की झड़प की आवाज सुनकर जंगल में भाग गए और अपने पीछे हथियार व गोला बारूद छोड़ गए जिसे वे उड़ा कर लाये थे ।

इस मुठभेड़ में श्री एल० बीरा सिंह ने प्रशंसनीय साहस एवं पहलशक्ति का प्रदर्शन किया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4 फरवरी, 1969 से दिया जायेगा ।

सं० 68-प्रेज/69.—राष्ट्रपति मैसूर पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री ख्वाजा निज़ामुद्दीन,
हैड कांस्टेबल सं० 117,
यादगीर, जिला गुलबर्गा,
मैसूर । **(स्वर्गीय)**

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

28 जुलाई, 1964 को जिला गुलबर्गा के कथीकूनी ग्राम के मैरिगैमा मंदिर में अनेक पशुओं की बलि देने का फैसला किया गया । अनेक व्यक्तियों ने बहुसंख्या में पशुओं की इस बलि का विरोध किया क्योंकि यह कानून के विरुद्ध भी था । श्री ख्वाजा निज़ामुद्दीन को दो पुलिस कांस्टेबलों के साथ पशुओं की बलि रोकने के लिए नियुक्त किया गया । श्री निजामुद्दीन ने थाने के सब-इन्सपैक्टर को साथ लेकर ग्राम के वयोवृद्ध व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित किया और उन्हें पशुओं का बध न करने की सलाह दी । किन्तु 28 जुलाई, 1964 को एक विशाल जुलूस मंदिर पर जमा हो गया जो अपने साथ अनेक भैंसे और बकरियां बलि के लिए लाया था । धक्का-मुक्की में श्री निज़ामुद्दीन पुलिस दल के अन्य सदस्यों से अलग हो गए । कर्त्तव्य-परायणता की चिन्ता में उन्होंने लोगों से पशुओं का बध न करने की बिनती की । किन्तु, किसी ने उनकी नहीं सुनी । इसके विपरीत भीड़ की ओर से उत्तेजनात्मक प्रबोधन हुए कि उन्हें पुलिस के सामने नहीं झुकना चाहिए और देवी को पशुओं की बलि देकर प्रसन्न करना चाहिए । श्री ख्वाजा निज़ामुद्दीन से व्यक्तियों ने हाथापाई की । उन्होंने अपनी बन्दूक भरने की कोशिश की किन्तु भीड़ ने उन पर प्रहार किया और उन्हें लाठियों से खूब पीटा जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गहरी चोटें आईं और वे मूर्छित होकर गिर पड़े तथा बाद में उन चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई । श्री ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने कर्त्तव्य-परायणता में अपनी जान न्योछावर कर दी ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृति भत्ता भी दिनांक 28 जुलाई 1964 से दिया जाएगा ।

नागेन्द्र सिंह, राष्ट्रपति के सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 1969

संकल्प

सं० 3-8/69-एफ०—केन्द्रीय वन मंडल ने अपनी 20-22 जनवरी, 1965 की बैठक में अन्य बातों के साथ 2 यह सिफारिशें की थीं कि मंडल को विशेष रूप से विशेषज्ञों की सहायता प्रदान की जानी चाहिए । यह पैनल समय-समय पर वनशिक्षा के क्षेत्र में सब समस्याओं की क्रम-बद्ध रूप में छान-बीन का कार्य करेगा । तदनुसार, इस विभाग के संकल्प सं० 3-19/65-एफ०दिनांक 29-12-1965 द्वारा केन्द्रीय वन मंडल की वन विज्ञान शिक्षा का एक पैनल बनाया गया । पैनल की 3 साल की अवधि की समाप्ति पर 12-11-1969 से इस के पुनर्गठन का निर्णय किया गया है । पुनर्गठित पैनल का गठन इस प्रकार होगा :—

गठन

अध्यक्ष

1. वन महानिरीक्षक

सदस्य

2. अध्यक्ष, वन अनुसन्धान संस्थान और महाविद्यालय, देहरादून ।
3. वन शिक्षा निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय, देहरादून ।
4. श्री एम० बी० रायज़ादा, प्रिंसिपल, डी० ए० वी० कालेज, देहरादून ।
5. श्री टी० एन० श्रीवास्तव, महावनपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6. श्री टी० जयदेव, महावनपाल, मद्रास ।
7. श्री के० एल० लहरी, महावनपाल, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता ।

सदस्य सचिव

8. वन उप महानिरीक्षक

कार्य

पैनल का कार्य साधारणतया देश की वन-विज्ञान शिक्षा की नीती में केन्द्रीय वन मंडल का मार्गदर्शन करना होगा । विशेष रूप से निम्नलिखित कार्य में:—

(1) वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय, देहरादून में वन-विज्ञान शिक्षा सम्बन्धी सब मामले ;

(2) भारतीय वन महाविद्यालय और रेंजर्स महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों और भारत में वन विज्ञान तथा सम्बन्धित विषयों में प्रशिक्षण के अन्य पाठ्यक्रमों का आवधिक परिशोधन;

(3) भारत में वन विज्ञान तथा सम्बन्धित विषयों के प्रशिक्षण और शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के नियमों में संशोधन के सुझाव; और

(4) वन विज्ञान में विदेशी डिग्रियों और डिप्लोमों के मूल्यांकन में और ऐसी डिग्रियों तथा डिप्लोमों को उचित मान्यता प्रदान करने के बारे में भारत सरकार को सलाह देना ।

क्रियाविधि की नियमावली

साधारणतः पैनल की एक साल में दोबार बैठकें होंगी और प्रत्येक 3 साल के बाद इस का पुनर्गठन किया जायेगा । आवश्यकता पड़ने पर पैनल के अध्यक्ष को अन्य सदस्य सहयोजित करने का अधिकार होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों और विभागों, समस्त राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, योजना आयोग, मन्त्रीमंडल सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियन्त्रक और महा लेखापाल, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग) के सब सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा पैनल के समस्त सदस्यों को भेज दी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशन किया जाये ।

म० ला० विधानी, उप-सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर 1969

संकल्प

सं० 4-15/68-भूमि—खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) के संकल्प सं० 6-6/67-जनरल II दिनांक 27 जुलाई, 1967, संकल्प संख्या 4-15/68-भूमि दिनांक 5 मार्च, 1968, 24 जुलाई, 1968, 28 नवम्बर, 1968, 15 मार्च 1969, 5 जून, 1969 तथा 15 सितम्बर, 1969 द्वारा भारत सरकार ने जो भूमि अर्जन पुनर्विचार समिति, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, के समस्त ढांचे को शीघ्रता से विकसित होने वाली अर्थ व्यवस्था के संदर्भ में परीक्षा करने हेतु नियुक्त की थी, उसे अपनी रिपोर्ट 30 नवम्बर 1969 तक प्रस्तुत करनी थी । अब भारत सरकार के उस समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि को 31 जनवरी 1970 तक बढ़ा देने का निश्चय किया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि अध्यक्ष तथा भूमि अर्जन समिति के सदस्यों को, भारत सरकार के समस्त मन्त्रालयों, विभागों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, मन्त्रीमंडल सचिवालय, भारत सरकार के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, समस्त राज्यों और संघ क्षेत्र के राजस्व सचिवों, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसद पुस्तकालय को भेजा जाए ।

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

शरण सिंह संयुक्त सचिव

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 1969

सं० 28-1/69-समन्वय/भा० कृ० अनु० परि०—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की नियमावली के नियम 75 में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार खाद्य तथा कृषि मंत्री ने निम्नलिखित व्यक्तियों को दिनांक 19 नवम्बर, 1969 से तीन वर्ष की अवधि के लिए परिषद् की कृषि अर्थशास्त्र, सांख्यिकी तथा विपणन अनुसंधान की स्थायी समिति का सदस्य सहर्ष मनोनीत किया है ।

सदस्यों के नाम

1. श्री एस० के० एस० चिब, सचिव, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली ।
2. डा० डी० के० देसाई, प्रोफेसर, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद ।
3. डा० डब्ल्यू० डेविड हाप्पर, कृषि अर्थशास्त्री, भारतीय कृषि कार्यक्रम, दी राक फैलर फाउन्डेशन, नई दिल्ली ।
4. डा० ए० एस० काहलों, डीन, कालिज आफ बेसिक साईन्सेज एण्ड ह्यूमैनिटीज, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना ।
5. डा० के० कानूनगी, कृषि प्रमुख, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
6. प्रो० पी० एन० माथुर, निदेशक, गोखले इंस्टीट्यूट आफ पालिटिक्स एण्ड इकानामिक्स, पूना ।
7. डा० अशोक मेहता, अध्यक्ष, कृषि मूल्य आयोग, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग), भारत सरकार नई दिल्ली ।
8. श्री एच० डी० शौरी, महानिदेशक, विदेशी व्यापार संस्थान, नई दिल्ली ।

सदस्य पदेन

9. कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास, तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग), भारत सरकार, फरीदाबाद ।
10. निदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन सांख्यिकी विभाग, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
11. अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकीय सलाहकार, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली ।
12. उप-महानिदेशक (फसल विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ।
13. उप-महानिदेशक (भू, सस्य विज्ञान एवं इंजीनियरिंग), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ।
14. उप-महानिदेशक (पशु विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ।
15. उप-महानिदेशक (शिक्षा एवं केन्द्र राज्य सम्बन्ध), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ।
16. निदेशक, कृषि अनुसंधान सांख्यिकी संस्थान, नई दिल्ली ।
17. सांख्यिकीय सलाहकार, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, बम्बई ।
18. अध्यक्ष, कृषि अर्थशास्त्र, सांख्यिकी एवं विपणन वैज्ञानिक पैनल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ।

उपरोक्त नियमावली के नियम 76 के अनुसार महा-निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् स्थायी समिति के क्रमशः अध्यक्ष तथा सचिव होंगे ।

मधुसूदन रामचन्द्र कोल्हटकर, उप-सचिव

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवम्बर 1969.

सं० 14/4/65-सी० 5 (सी० ए० 1-2)—इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० एफ० 14-4/65 सी० 5(सी० ए० 1-2), दिनांक 30 सितम्बर, 1969, के क्रम में डा० अके क्रोमनाऊ, अभिलेख महानिदेशक, स्टाकहोम (स्वीडन), को भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के संवादी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है । फिलहाल उनकी नियुक्ति की अवधि 3-4-1971 तक होगी ।

ए० एस० तलवार, अवर सचिव,

सिंचाई तथा बिजली मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 1969

संकल्प

सं० बिजली-दो-19(1)/66—सिंचाई व बिजली मंत्रालय ने संकल्प सं० 19 (1)/66–बिजली-दो दिनांकित 10 मई, 1966 के अंतर्गत, बिजली की अन्तर्राज्यीय सप्लाई के लिए उपयुक्त टैरिफ के निर्धारण हेतु सम्यक सिद्धांत और मार्गदर्शक नियम बनाने के लिए एक समिति स्थापित की थी । समिति की सिफारिशें 6 जून, 1967 और 26 अगस्त, 1967 को राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों को परिपत्रित की गई थीं । समिति की सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(1) बिजली की अंतर्राज्यीय सप्लाई को निम्नलिखित कोटियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(क) तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दीर्घ-कालीन बिजली सप्लाई;

(ख) तीन वर्ष से कम की अवधियों के लिए अस्थायी बिजली सप्लाई;

(ग) मौसिमी बिजली सप्लाई ;

(घ) अंत: संबद्ध प्रणालियों के बीच बिजली का विनिमय जिससे प्रादेशिक प्रणालियों का समेकित प्रचालन उत्पन्न होगा,

(ङ) "संकट" बिजली सप्लाई (अर्थात उत्पादन संयंत्र/पोरषण सुविधाओं के भंग होने से उत्पन्न होने वाली आपातकालीन मांगें, इत्यादि); और

(च) प्रतिबंधित बिजली सप्लाई (उच्चतम भार के समय और दूसरे समय) ।

(2) उत्पादन और पोरषण की लागतें बिजली (सप्लाई) अधिनियम, 1948 की क्रमशः आठवीं और पांचवीं अनुसूचियों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर निकाली जानी चाहिए ; उक्त अधिनियम में बोर्डों के लिए समुपयुक्त आधार पर ब्याज और मूल्य ह्रास के संबंध में उपयुक्त तरमीमें कर दी गई हैं।

(3) अंतर्राज्यीय सप्लाई की लागत उत्पादन की समेकित लागत पर (जिसमें यदि कोई बिजली खरीदी गई हो तो उसकी लागत भी शामिल हो) और उस ग्रिड पोरषण की उपयुत लागत पर आधारित होनी चाहिए जिससे विक्रेता बोर्ड बिजली सप्लाई करता है।

(4) कोटि (क) के लिए टैरिफ, सप्लाई की लागत पर आधारित होना चाहिए और उसमें 3 प्रतिशत लाभ-तत्व भी शामिल होना चाहिए। (ऐसा इसलिए है क्योंकि उपर्युक्त कोटि (क) के अंतर्गत विक्रेता बोर्ड को अपेक्षित उत्पादन क्षमता प्रतिष्ठापित करनी होती है और खरीददार बोर्ड के लिए दीर्घकालीन आधार पर इस प्रकार की क्षमता सुरक्षित रखनी होती है और वह विक्रेता बोर्ड के क्षेत्र के भीतर ही थोक उपभोक्ता को सप्लाई की जाने वाली बिजली के मामलों में समान ही होती है। इसलिए सप्लाई की लागत पूरी की पूरी हिसाब में ली जानी चाहिए और साथ ही बिजली सप्लाई की के लिए शुल्क निर्धारित करने के उद्देश्य से 3 प्रतिशत लाभ-तत्व भी लगाना चाहिए।)

(5) कोटि (ख) से (ङ) तक के लिए टैरिफों में केवल सप्लाई की लागत ही हिसाब में ली जानी चाहिए, अर्थात 3 प्रतिशत लाभ-तत्व निकाल कर केवल उत्पादन और पोरषण की लागत।

(6) कोटि (च) के लिए टैरिफ, खरीददार और विक्रेता बोर्डों को आपस में तय कर लेना चाहिए क्योंकि व्यस्ततम घंटों और अन्य घंटों के दौरान सप्लाई की लागत संबंधित बोर्डों द्वारा आपसी बातचीत से निर्धारित की जा सकती है।

(7) कोटि (क) और (ख) के मामले में द्विभागीय टेरिफ अपनाया जा सकता है और अन्य कोटियों के बारे में केवल ऊर्जा शुल्क अपनाए जा सकते हैं।

(8) यदि किसी विशेष मामले में विद्यमान दशाएं समिति द्वारा सिफारिश की गई किसी भी कोटि के अंतर्गत नहीं आतीं तो विक्रेता और खरीददार बोर्डों को आपसी बातचीत द्वारा एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य टैरिफ निश्चित कर लेना चाहिए।

(9) जहां तक अंतर्राज्यीय बिजली सप्लाई पर ड्यूटी/कर लगाने का संबंध है, भारत सरकार इस मामले को संविधान के संगत उपबंधों के संदर्भ में राज्य सरकारों के साथ उठा सकती है।

(10) ये सिफारिशें एक ओर सरकारी विभागों और निगम-निकायों और दूसरी ओर राज्य बिजली बोर्डों के बीच होने वाले बिजली के क्रय विक्रय पर स्वतः लागू नहीं होती।

2. समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों के प्रतिनिधियों की निम्नलिखित क्षेत्रीय बैठकों में विचार-विमर्श किया गया था : 5 मार्च, 1968 (उत्तरी क्षेत्र), 13 मार्च, 1968 (पूर्वी क्षेत्र), 22 मार्च, 1968 (दक्षिणी क्षेत्र), 27 मार्च, 1968 (पश्चिमी क्षेत्र) और 17 अप्रैल, 1968 (उत्तर-पूर्वी-क्षेत्र)। तदनंतर इन सिफारिशों पर 26 और 27 मई, 1969 को नैनीताल में हुए राज्यों के सिंचाई व बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श हुआ। समिति के सुझावों को निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया है :

(i) सुझाव संख्या 5 के संबंध में यह फैसला किया गया कि विभिन्न कोटियों के लिए निम्नलिखित लाभ-तत्व को शामिल कर लिया जाए :—

कोटि (ख)—3 वर्षों से कम अवधि के लिए अस्थायी बिजली सप्लाई।

(i) 1 वर्ष तक —1 प्रतिशत लाभ
(ii) 2 वर्ष तक —2 प्रतिशत लाभ
(iii) 3 वर्ष तक —3 प्रतिशत लाभ

कोटि (ग)—मौसिमी सप्लाई—1/2 प्रतिशत लाभ

कोटि (घ)—क्षेत्रीय प्रणालियों के समेकित प्रचालन के लिए अंतः संबंध प्रणालियों के बीच विद्युत विनिमय—1/2 प्रतिशत

कोटि (ङ)—आपत्कालीन बिजली सप्लाई—कोई भी लाभ-तत्व शामिल नहीं किया जाना है।

(ii) अन्तर्राज्यीय बिजली विक्रय पर ड्यूटी अथवा कर लगाने से संबद्ध सुझाव 9 के संबंध में आम राय यह थी कि अन्तर्राज्यीय विद्युत विक्रय पर कोई डियूटी कर न लगाया जाए।

(iii) क्षेत्रीय स्तरों पर विचार विमर्श करने के पश्चात निम्नलिखित एक और सुझाव दिया गया है :—

"जब विभिन्न व्याख्याओं और परिकलनों के संबंध में मतभेद के परिणाम स्वरूप कोई विवाद उठ खड़ा हो, उसे केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण को निर्दिष्ट कर दिया जाए जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा"

3. भारत सरकार ने समिति के सुझावों और उपर्युक्त संशोधनों को स्वीकर कर लिया है और उनको राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों की स्वीकृति के लिए भेज दिया है। केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग को आदेश दे दिए गए हैं कि वे इस संकल्प के अनुसार बिजली के अन्तर्राज्यीय विक्रय के लिए अपयुक्त टैरिफ निर्धारित करने में राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों को सहायता दें।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए और इसकी एक प्रति सभी संबंधित कार्यालयों को भेज दी जाए।

वी० वी० चारि, सचिव

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 3 दिसम्बर 1969

संशोधन

सं० 4/7/68—सी० आई० एस—केन्द्रीय सूचना सेवा के चतुर्थ ग्रेड की अस्थायी रिक्तियों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अप्रैल, 1969 में ली गई प्रतियोगिता परीक्षा संबंधी

21 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित नियमावली के नियम 9 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

नियम 9 की वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएं:-

"उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें ऐसी कोई शारीरिक कमी नहीं होनी चाहिए जिससे वह इस सेवा के अधिकारों के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलता से न निभा सके। यदि सरकार या नियुक्ति अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निर्धारित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका है, तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को डाक्टरी परीक्षा देनी होगी।"

भगवती शरण सिंह, उप सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 3rd December 1969

No. 67-Pres./69.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Manipur Rifles :—

Name of the officer and rank

Shri L. Bira Singh,
Havildar No. 1096,
2nd Battalion, Manipur Rifles,
Imphal.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 29th January 1969, a large gang of hostiles raided the village of Monghlam and took away some rifles belonging to the Village Volunteer Force. A Platoon of 2nd Battalion of Manipur Rifles under the command of Shri L. Bira Singh, Havildar, was deputed to intercept the hostiles and to recover the rifles. On the 4th February 1969, information was received that the gang was likely to be in village Molkot which is situated on a steep hill. Undeterred by its small strength and limited fire power, the Platoon proceeded to Molkot. On approaching the village, a hostile sentry was observed. Shri Bira Singh advanced stealthily towards the sentry in order to overpower him. While doing so, he was noticed by a girl who screamed. The sentry also became alert, but Shri Bira Singh, without caring for his personal safety, threw himself on the sentry and overpowered him. The other hostiles on hearing the screams of the girl and the noise of the scuffle fled into the jungle, leaving behind the arms and ammunition which they had carried off.

In this encounter, Shri L. Bira Singh displayed commendable courage and initiative.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 4th Februaary, 1969.

No. 68-Pres./69.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Mysore Police :—

Name of the officer and rank

Shri Khaja Nizamuddin,
Head Constable No. 117,
Yadgir, District Gulabarga,
Mysore. (*Deceased*)

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 28th July, 1964 the villagers of Kathikuni village, District Gulabarga, decided to sacrifice a large number of animals at Marigamma Temple. A section of the people protested against this large-scale sacrifice of animals, which was also against the law. Shri Khaja Nizamuddin, alongwith two Police Constables was deputed to prevent animals being sacrificed. Shri Nizamuddin, alongwith the Sub-Inspector of the Police Station, contacted the elders in the village and advised them not to kill the animals. But on the 28th July, 1964, a big procession converged on the Temple and brought with them several buffaloes and goats for the sacrifice. In the melee, Shri Nizamuddin was separated from the other members of the Police party. In his anxiety to discharge his duty, he again appealed to the people not to kill the animals. But no one listened to him. On the contrary, there were frenzied exhortations from the crowd that they should not yield to the Police and the deity must be appeased by offering animals as sacrifice. Shri Khaja Nizamuddin was manhandled by the people. He tried to load his musket but the crowd attacked, and belaboured him with lathis as a result of which he received severe injuries and fell down unconscious and subsequently succumbed to the injuries. Shri Khaja Nizamuddin laid down his life in the discharge of his duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 28th July, 1964.

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 21st November 1969

Appointment of Valuers u/s 4(3) of the Estate Duty Act, 1953.

No. 5/77/68-E.D.—In partial modification of this Ministry's Notice of even number dated 6-7-1968, it is hereby notified for general niformation that in order to be eligible for appointment as a Valuer in the category of "Engineer, Surveyor or Architect", a person must satisfy the following qualifications :

(i) The valuer must either be a graduate in Engineering Mining or Architecture of a recognised University, or be a member or hold a diploma of a recognised Institute or Institution of Engineers, Architects, Surveyors or School of Mines, the membership or diploma of which is recognised as sufficient qualification for the purposes of recruitment to superior posts and services under the Central Government; and

(ii) he must have been in practice as consulting engineer, mining engineer, surveyor or architect for not less than seven years.

N.B.—For the purposes of clause (ii) above, continuous service of seven years in the following capacities, would be considered as equivalent to seven years' practice :—

(a) a State or the Central Government, as a gazetted officer;

(b) a Statutory Improvement Trust, Municipality, Municipal Corporation or a District Board as a member of the Executive staff engaged on valuation work; and

(c) a business or professional organisation, in any capacity, not below the rank of a Deputy Chief Engineer, provided the organisation had a turnover of not less than Rs. 50 lakhs or a net income of not less than Rs. 10 lakhs, in each of the last three accounting years (ending with the year in which the applicant ceased to be an employee in the cases of persons who are no longer in employment).

BALBIR SINGH, Dy. Secy.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY

(Department of Foreign Trade)

New Delhi, the 28th November 1969

No. 4(27)-*TEX*(*C*)/69.—The Government of India direct that the following amendment shall be made in their Resolution No. 4(27)-TEX(C)/69, published in the Gazette of India Extraordinary dated the 17th May, 1969 :

Against Serial No. (2) : Vice-Chairman,

For Additional Textile Commissioner,

please *read* Joint Textile Commissioner.

A. G. V. SUBRAHMANIAM, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

RESOLUTION

New Delhi, the 3rd December 1969

No. 20-1/69-*L.D.III.*—Consequent on the dissolution of the Central Council of Gosamvardhana with effect from 1st December, 1969 *vide* this Ministry Resolution No. 20-20/69-L.D.III., dated the 29th October, 1969, the Government of India hereby take over all the properties of the Council as referred to in para 2(b) of the Resolution and also designate, Director of Administration, Directorate of Extension, Department of Agriculture, to arrange for their disposal in the manner deemed fit.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories and the Departments of the Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and Director of Administration, Directorate of Extension, Department of Agriculture.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. P. GULATI, Dy. Secy.

RESOLUTION

New Delhi, the 4th December 1969

No. 3-8/69-*F.*—The Central Board of Forestry in its meeting held on 20th-22nd January, 1965, *inter-alia* recommended that the Board should be provided expert assistance from a specially constituted Panel which would undertake a systematic scrutiny of all problems in the field of Forestry Education from time to time. Accordingly, a Panel on Forestry Education of the Central Board of Forestry was constituted in 1965 *vide* this Department's Resolution No. 3-19/65-F., dated the 29th December, 1965. On the expiry of the term of three years for the Panel, it has been decided to reconstitute it with effect from the 12th November, 1969. The composition of the reconstituted Panel will be as under :—

Composition

Chairman

1. Inspector General of Forests.

Members

2. The President, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun.
3. The Director of Forest Education, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun.
4. Shri M. B. Raizada, Principal, D.A.V. College, Dehra Dun.
5. Shri T. N. Srivastava, Chief Conservator of Forests, U.P., Lucknow.
6. Shri T. Jayadev, Chief Conservator of Forests, Madras.
7. Shri K. L. Lahiri, Chief Conservator of Forests, West Bengal, Calcutta.

Member-Secretary

8. Deputy Inspector General of Forests.

Functions

The functions of the Panel shall be to assist the Central Board of Forestry, generally in guiding the country's policy on Forestry Education, particularly in :

(i) all matters concerning Forestry Education at the Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun;

(ii) revising periodically the sylabii of the Indian Forest College, the Rangers' Colleges and other Courses of the training in Forestry and allied subjects in India;

(iii) suggesting amendments to Rules on various courses of training and education concerning forestry and allied subjects in India; and

(iv) advising the Government of India in evaluating foreign degrees and diplomas in forestry and in according appropriate recognition to such degrees and diplomas.

Rules of Procedures

The Panel shall normally meet twice a year and shall be reconstituted after every 3 years. The Chairman of the Panel shall have the power to co-opt additional members as and when required.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries and Departments of Government of India, all the State Governments, Union Territories, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Raiya Sabha Secretariat, Lok Sabha Secretariat; Prime Minister's Secretariat, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, all attached and Subordinate offices of the Ministry of Food, Agriculture, C.D. & Coopn., (Department of Agriculture). All members of the Panel.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

M. L. WIDHANI, Dy. Secy.

New Delhi, the 6th December 1969

RESOLUTION

No. 4-15/68-*Lands.*—The Land Acquisition Review Committee appointed by the Government of India *vide* Resolution No. 6-6/67-Genl.II, dated the 27th July, 1967 read with Resolution No. 4-15/68-Lands, dated the 5th March, 1968, 24th July, 1968, the 28th November 1968, the 15th March, 1969, the 5th June 1969 and the 15th September 1969 of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture), for examining the entire frame work of the Land Acquisition Act, 1894 in the context of a rapidly developing economy, was required to submit its report by the 30th November 1969. The Government of India has now decided to extend the date for submission of the Report by the Committee to 31st January 1970.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to the Chairman and Members of the Land Acquisition Review Committee, All Ministries/Departments of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the President's Secretariat, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Revenue Secretaries in all State and Union Territories, the Lok Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat, Parliament Library.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SARAN SINGH, Jt. Secy.

(Indian Council of Agricultural Research)

New Delhi, the 3rd December 1969

No. 28(1)/69-CDN.(I)/ICAR.—Under the provisions of Rule 75 of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research, the Minister of Food and Agriculture has been pleased to nominate the following to be members of the Standing Committee for Agricultural Economic, Statistical and Marketing Research of the Society for a period of three years with effect from the 19th November, 1969 :—

Members by Name

1. Shri S. K. S. Chib, Secretary, National Cooperative Development Corporation, New Delhi.
2. Dr. D. K. Desai, Professor, Indian Institute of Management, Ahmedabad.
3. Dr. W. David Hopper, Agricultural Economist, Indian Agricultural Programme, The Rockfeller Foundation, New Delhi.
4. Dr. A. S. Kahlon, Dean, College of Basic Sciences and Humanities, Punjab Agricultural University, Ludhiana.
5. Dr. K. Kanungo, Chief Agriculture, Planning Commission, Government of India, New Delhi.
6. Prof. P. N. Mathur, Director, Gokhale Institute of Politics and Economics, Poona.
7. Dr. Ashok Mitra, Chairman, Agricultural Prices Commission, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture), Government of India, New Delhi.
8. Shri H. D. Shourie, Director General, Institute of Foreign Trade, New Delhi.

Members by Designation

9. The Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture) Government of India, Faridabad.
10. The Director, Central Statistical Organisation, Department of Statistics, Cabinet Secretariat, Government of India, New Delhi.
11. The Economic and Statistical, Adviser, Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture), Government of India, New Delhi.
12. Deputy Director General (Crop Sciences), Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
13. Deputy Director General (Soils, Agronomy and Engineering) Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
14. Deputy Director General (Animal Sciences), Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
15. Deputy Director General (Education and Centre-State Relations), Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
16. The Director, Institute of Agricultural Research Statistics, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
17. The Statistical Adviser, Reserve Bank of India, Bombay.
18. Chairman, Scientific Panel for Agricultural Economics, Statistics and Marketing, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

Under the provisions of Rule 76 of the Rules referred to above, Director General, Indian Council of Agricultural Research and Secretary, Indian Council of Agricultural Research shall be the Chairman and the Secretary of the Standing Committee respectively.

M. R. KOLHATKAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES

New Delhi, the 29th November 1969

No. F. 14/4/65-C.5(CAI-2).—In continuation of this Ministry's Notification No. F. 14-4/65-C.5(CAI-2), dated the 30th September, 1969, Dr. Ake Kromnow, Director General of Archives, Stockholm (Sweden), is appointed as a Corresponding Member of the Indian Historical Records Commission. The term of his appointment will for the present be up to 3-4-1971.

A. S. TALWAR, Under Secy.

RESOLUTION

New Delhi, the 5th December 1969

SUBJECT :—*The National Board of Adult Education.*

No. F. 18-1/69-SE.I.—"Liquidation of mass illiteracy is necessary", says the Government Resolution on National Policy on Education, "not only for promoting participation in the working of democratic institutions and for accelerating programmes of production, especially in agriculture, but for quickening the tempo of national development in general'. Accordingly, importance is being given in the Fourth Five Year Plan to programmes of adult education, including those for the spread of literacy. "Efforts will be made", it says, "to spread literacy amongst adults through mobilisation of voluntary efforts and local community resources. Pilot projects will be initiated in selected districts to begin with and the programme will be extended to other areas in the light of the experience gained. For the development of the programme, assistance will be sought from industry, from the students working under the National Service Scheme, and from voluntary organisations who will be assisted financially and given technical guidance. The programmes of Farmers' Education and Functional Literacy in the high-yielding variety areas, already mentioned under Agriculture, will be extended to 100 districts and will cover one million adult farmers. Adult education will continue to be an integral part of the community development programme. The University Departments of Adult Education will be helped to take up pilot projects, to conduct research and organise extension and extra-mural lectures".

2. It is necessary to create an organisation at the national level to promote, guide and evaluate these programmes. This subject had been discussed earlier and the National Seminar on Liquidation of Illiteracy held at Poona in 1965, recommended the establishment of a National Board of Adult Education. The Education Commission (1964-66) also endorsed this recommendation. The Government of India have accepted these proposals and have decided to establish a National Board of Adult Education.

3. The Board shall consist of the following members :

1. The Union Minister of Education & Youth Services. *Chairman*
2. Secretary, Ministry of Education & Youth Services.
3. One representative each of the following Ministries of the Government of India, namely,
   (a) Information & Broadcasting;
   (b) Food & Agriculture;
   (c) Ministry of Law (Department of Social Welfare);
   (d) Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour & Employment);
   (e) Health, Family Planning & Urban Development;
   (f) Railways; and
   (g) Steel and Heavy Engineering.
4. One representative of the Planning Commission;
5. Ministers of State Governments and Union Territories dealing with adult education and the Chief Executive Councillor, Delhi;

6. One representative each of University Grants Commission, Inter-University Board and the Central Social Welfare Board;

7. Not more than 20 persons nominated by the Chairman of the Board to represent educationists, local authorities, organisations of industrial workers and farmers and voluntary organisations engaged in the field of adult education; and

8. Director, Bureau of Planning & Coordination, Ministry of Education & Youth Services.—*Member-Secretary*

4. The terms of office of the members of the Board, other than *ex-officios* shall be three years from the date on which its 1st meeting is held. Outgoing members shall be eligible for renomination for another term.

5. The functions of the Board of Adult Education (which will include the spread of literacy and organisation of library services would be the following :—

(1) To advise the Government of India, the State Governments and the Union Territory Administrations on all matters relating to adult education;

(2) to promote adult education, to draw up policies and programmes in these fields and to review their progress from time to time;

(3) to ensure coordination between the different agencies, official and non-official, working in the field of adult education.

(4) to promote the production of literature and other teaching materials for adult education;

(5) to act as a clearing house of ideas, information and experience in the field of adult education and to mobilise manpower and resources for promoting adult education;

(6) to promote research, investigation and evaluation in adult education; and

(7) generally to advise, assist or undertake all allied activities and programmes as will promote adult education.

6. The Board will set up such committees as may be necessary for (1) Literacy Programmes, (2) Library Services, (3) Production of Literature and Training and (4) Continuing Education. The composition and terms of reference of these committees, which might include co-opted experts in the field, will be decided by the Chairman of the Board from time to time.

7. The Board will have a Standing Committee consisting of :—

(a) The Chairman of the Board;

(b) Chairman of the Committees of the Board on Literacy; Library Services, and Production of Literature and Training and Continuing Education;

(c) Not more than five members of the Board nominated by the Chairman; and

(d) Member-Secretary.

8. The Board shall have powers to frame rules and regulations for the transaction of its business as well as that of its committee.

9. The Board shall meet as often as necessary but not less than once a year.

10. The Department of Adult Education of the N.C.E.R.T. shall provide the necessary secretary and academic services to the Board.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be sent to all State Governments, Union Territory Administrations, all Ministries of the Government of India, University Grant Commission, Planning Commission, Prime Minister's Secretariat, New Delhi.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

S. CHAKRAVARTI, Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 27th November 1969

RESOLUTION

No. EL.II-19(1)/66(.).—The Ministry of Irrigation & Power, *vide* Resolution No. 19(1)/66-EL.II, dated the 10th May, 1966, set up a Committee to evolve sound principles and guidelines for fixation of suitable tariff for inter-State supply of power. The recommendations of the Committee were circulated to State Governments and State Electricity Boards on 8th June, 1967 and 26th August, 1967. The recommendations of the Committee are given below :—

(1) Inter-State supplies of power may be classified under the following categories :

(a) Long-term power supply for period of three years and more;

(b) Temporary power supply for periods below three years;

(c) Seasonal power supply;

(d) Exchange of power between inter-connected systems leading to integrated operation of regional systems;

(e) "Distress" power supply (*i.e.*, emergent demands resulting from breakdown of generating plant and/or transmission facilities etc.); and

(f) Restricted power supply (peak or off-peak hours).

(2) Costs of generation and transmission should be worked out on the principles laid down in the Eighth and the Fifth Schedules to the Electricity (Supply) Act, 1948, respectively, suitably modified in respect of interest and depreciation on the lines appropriate to the Boards.

(3) The cost of inter-State supply should be based on the pooled cost of generation (including the cost of power purchased, if any) and the appropriate cost of transmission of the grid from which the selling Board supplies power.

(4) The tariff for category (a) should be based on the cost of supply and also include the 3 per cent profit element. (This is because, under category (a), mentioned above, the selling Board has to instal the required generating capacity and the reserve such capacity for the purchasing Board on a long-term basis, and is similar to the cases of power supply to a bulk consumer within the area of the selling Board. The cost of supply should, therefore, be taken into account in full as also 3 per cent profit element for the purposes of fixing charges for power supply).

(5) The tariff for categories (b) to (e) should take into account the cost of supply only *i.e.*, the cost of generation and cost of transmission only and excluding the 3 per cent profit element.

(6) The tariff for category (f) should be negotiated by the purchasing and selling Boards as the cost of supply during peak hours and off-peak hours may have to be determined by the concerned Boards by negotiations.

(7) Two-part tariff may be adopted in the case of categories (a) and (b) and energy charges only may be adopted in respect of the other categories.

(8) If the conditions obtaining in any special case are not adequately covered by any of the categories recommended by the Committee, the selling and purchasing Boards should arrive at a mutually acceptable tariff by negotiation.

(9) As regards the levy of duty/tax on inter-State power supplies, the Government of India may take up the matter with the State Governments in the context of the relevant provisions of the Constitution.

(10) These recommendations do not apply *ipso facto* to the purchase or sale of power as between Government departments and Corporate bodies on the one hand and the State Electricity Boards on the other.

2. The recommendations of the Committee were discussed at Regional meetings of representatives of State Governments and State Electricity Boards on 5th March, 1968 (Northern Region), 13th March, 1968 (Eastern Region), 22nd March, 1968 (Southern Region), 27th March, 1968 (Western Region) and 17th April, 1968 (North-Eastern Region). The recommendations were thereafter discussed at the Conference of State Ministers of Irrigation and Power held at Nainital on 26th and 27th May, 1969. The recommendations of the Committee have been accepted with the following modifications :—

(i) In regard to recommendation No. 5, it was decided that the following profit element may be included for different categories :—

For category (b)—temporary power supply for periods below 3 years :—

(i) Up to 1 year—1% profit

(ii) Up to 2 years—2% profit

(iii) Up to 3 years—3% profit

For category (c)—seasonal supply—½% profit

For category (d)—exchange of power between interconnected systems leading to integrated operation of Regional Systems—½%.

For category (e)—distress power supply—no profit element to be included.

(ii) As regards recommendation No. 9, in respect of levy of duty or tax on inter-State sale of power, the general consensus was that no duty/tax should be levied on inter-State sale of power.

(iii) The following additional recommendation has been made after discussions at Regional levels :—

"In case of disputes arising out of different interpretations and calculations, the same may be referred to the Central Electricity Authority whose decision shall be acceptable to both the parties".

3. The Government of India have accepted the recommendations of the Committee and the modifications as indicated above and commends the same for acceptance by State Governments/State Electricity Boards. The Central Water and Power Commission have been directed to assist the State Governments/State Electricity Boards in fixing suitable tariffs for inter-State sale of power in accordance with this Resolution.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned.

V. V. CHARI, Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi-1, the 3rd December 1969

AMENDMENT

No. 4/7/68-CIS.—Rule 9 of the Rules for the competitive Examination held by the Union Public Service Commission in April, 1969, for the purpose of filling temporary vacancies in Grade IV of the Central Information Service published in the Gazette of India Part I, Section 1, dated the 21st September, 1968, is hereby amended as under :—

For the existing entries against rule 9, *read* :

"A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for *viva-voce* by the Commission may be required to undergo medical examination.

B. S. SINGH, Dy. Secy.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 6th December 1969

No. W. E. 48/36/69 dat.—In pursuance of rule 3(b) read with 4(iii) & (vi) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers' Education, the Government of India hereby appoints Shri B. V. Adavi, Deputy Secretary, Ministry of Finance (Department of Expenditure) as representative of the Ministry of Finance on the Central Board for Workers' Education *vice* Shri C. Venkataramani with effect from the date of this notification.

2. The following changes shall be made accordingly in the Ministry of Labour & Employment Notification No. E&P-4 (24)/58, dated the 12th December, 1958, published in the Gazette of India, Part I, Section 1, dated, December 20, 1958/Agrahayana 29, 1880 as amended from time to time :—

For the existing entry-:—

"3. Shri C. Venkataramani, Deputy Secretary, Ministry of Finance, (Department of Expenditure), New Delhi,

the following entry shall be *substituted* :—

"3. Shri B. V. Adavi, Deputy Secretary, Ministry of Finance, (Department of Expenditure), New Delhi."

HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969